प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | वर्ष : 61 ▪ अंक 09 ▪ 15 मार्च 2025 ▪ पृष्ठ-12 ▪ मूल्य - 3.00

प्रकाशन के 6 दशक

मोहन सरकार का मनमोहक बजट

लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ेंगे...

उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी

पेज- 2

2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया

बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया

केजरीवाल-सिसोदिया के बाद आतिशी, गोपाल राय निशाने पर!

14 कैग रिपोर्ट में पैसों की हेराफेरी

शराब घोटाले से बड़े एजुकेशन स्कैम का दावा

दिल्ली सरकार आप के दौर में हुए घोटालों की परतें खोलने की तैयारी में है। कुछ घोटाले पंजाब चुनाव के आसपास भी सामने लाए जाएंगे। इसमें से एक शिक्षा घोटाला भी हो सकता है।'दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है। ये शराब घोटाले के बराबर होगा। सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जब कैग की रिपोर्ट पेश होगी, तो बड़ी हेराफेरी सामने आएगी। मनीष सिसोदिया लिकर स्कैम में जेल गए थे, अब एजुकेशन स्कैम में जाएंगे।

कैसे हुआ 2002 करोड़ का शराब घोटाला?

विशेष रिपोर्ट

पेज-6-7-8

महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल!

फडणवीस-शिंदे के बीच टकराव तेज, कहीं बदल ना जाए महाराष्ट्र का समीकरण!

पेज- 9

मप्र में खपा दी छत्तीसगढ़ की 13 करोड़ की एक्सपायर्ड बियर

आबकारी विभाग की मिलीभगत से लोगों की जान से खिलवाड़, मामला मुख्य सचिव अनुराग जैन के संज्ञान में

निशाने पर पूरा विभाग...

पेज- 3

एक्सपायर्ड बीयर हो सकती है खतरनाक,बिगड़ सकता है स्वास्थ्य

टल गया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

अप्रैल में ऐलान संभव

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आरएसएस की बैठक के चलते देरी, महिला भी संभाल सकती है कमान

पेज- 05

पंजाब में गरमाई राजनीति 'मान नहीं दे रहे ध्यान'

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पहली बार पंजाब में दस्तक

पेज- 10

8 साल बाद भी राज...

सीडी किसने बनाई? किसने बंटवाइ?

कारोबारी की मौत, जेल से निकले बघेल सीएम बने और वर्मा सलाहकार

पेज- 11

चुभ गई कई बातें दिल में कई लहजे दिल में खंजर मार गए,
इस जिन्दगी के सफर में हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार गए।।

मोहन सरकार का मनमोहक बजट

लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ेंगे...

उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी

2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया

बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया

भोपाल। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि, उनको पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान जरूर हुआ है।वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाने की घोषणा भी की गई है। देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की। उन्होंने कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है...जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।उन्होंने बताया- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले।

वित्त मंत्री बोले... यह कर्ज नहीं है, निवेश है

बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- यह बात कही जाती है कि बजट जितने का है, उतने का कर्ज है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह कर्ज नहीं है, निवेश है। पिछली बार विभागों को जितना पैसा दिया था, उतना खर्च हुआ या नहीं हुआ...यह सब चिंता करके जीरो बजटिंग पर फोकस किया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जो कर्ज लिया है, उसे समय सीमा में चुका रहे हैं। विपक्ष के लोग बार-बार माथे पर गठरी लेकर कर्ज की बात करते हैं, हमें भी ठीक नहीं लगता कि उनके कार्यकाल को बार-बार याद दिलाएं। मुख्यमंत्री वे भी थे, खजाना उनका भी था लेकिन तब डेवलपमेंट नहीं होता था।

बजट में किसके लिए क्या

- बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। हितग्राहियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
- धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे।
- बजट में उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण

बजट में सरकार ने युवाओं पर भी ध्यान दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार छात्रावास का निर्माण करवाएगी। साथ ही प्रदेश में बीमा समिति का गठन किया जाए सीएम राइज स्कूल के लिए बजट में 1017 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर विस क्षेत्र में एक सर्वसुलभ स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

निजी निवेश से शासकीय संपत्ति का निर्माण

सरकार ने बजट में निजी निवेश से शासकीय संपत्ति का निर्माण योजना लेकर आई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्रावासों का निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में रुपए 26 हज़ार 797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रदेश में हवाई सफर और आसान होगा

प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मप्र के शहरों और देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है।

सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए

इसके साथ ही सिंहस्थ के लिए बजट 2025-26 में अलग से दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2025-26 में सड़क और पुल निर्माण के लिए 16436 करोड़ रुपए का प्रावधान है।वहीं, मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल बिछेगा। प्रदेश में 4251 करोड़ रुपए की लागत 116 नए रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है। इसके साथ ही रोड नेटवर्क के विस्तार के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं। इसके लिए फंड का प्रावधान किया गया है।

खेलों पर रहेगा जोर

खेलों को बढ़ावा देने के उद्दे श्य से सीएम युवा-शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्वसुलभ और सर्वसुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा

वित्त मंत्री देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- जितना पैसा केंद्र से आया, वही ईमानदारी से जनता पर खर्च किया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा वाली नीति पर काम किया है। यह विकास का बजट है। जनता का बजट है, जनता के लिए है। क्यूआर कोड के माध्यम से हमने बजट जनता तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तय की है। हम रेवेन्यू के नवाचार करने के पक्ष में हैं। इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हमारी आमदनी और कैसे बढ़े।

लाडली बहनों के लिए घोषणा

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पर एमपी का जोर रहेगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय को 22 लाख के पार पहुंचाना है। साथ ही अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार जनजाति वर्ग के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेगी। वहीं, लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।

सीएम ने कहा... बजट में विकसित मप्र 2047 का विजन

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट की सराहना की। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन रखा है, प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बंधित विवरण घोषणा

फार्म 4

1.	प्रकाशन स्थल	:	इन्दौर
2	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3	मुद्रक का नाम	:	विनोद खुजनेरी
	(क्या भारत का नागरिक है)	:	हां
	(पता)	:	204, शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इन्दौर
4	प्रकाशक का नाम	:	विनोद खुजनेरी
	(क्या भारत का नागरिक है)	:	हां
	पता:	:	204, शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इन्दौर
5	संपादक का नाम	:	विनोद खुजनेरी
	(क्या भारत का नागरिक है)	:	हां
	(पता)	:	204, शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इन्दौर
6	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	:	विनोद खुजनेरी 204, शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इन्दौर

मैं विनोद खुजनेरी एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक: 15.03.2025

हस्ताक्षर
विनोद खुजनेरी
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
15 मार्च 2025

मप्र में खपा दी छत्तीसगढ़ की 13 करोड़ की एक्सपायर्ड बियर

आबकारी विभाग की मिलीभगत से लोगों की जान से खिलवाड़, मामला मुख्य सचिव अनुराग जैन के संज्ञान में

भोपाल (विनोद उपाध्याय)। मप्र में शराब कारोबार से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें लाखों लीटर एक्सपायर्ड शराब की हेराफेरी की गई। सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश लाई गई 55,090 पेटी यानी करीब साढ़े चार लाख लीटर एक्सपायर्ड बियर का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा गया और बाद में उसे नष्ट करने का दावा किया गया। आबकारी विभाग के अधिकारियों और लिकर कंपनी ने सांठगांठ कर बड़ी मात्रा में एक्सपयर्ड बियर लाइसेंसी दुकानों से ग्राहकों को बेची गई। सरकारी दस्तावेजों में बताया गया कि यह शराब 4,20,94,970 रुपए (करीब 4.21 करोड़) की थी, लेकिन पड़ताल में सामने आया कि इसकी वास्तविक कीमत करीब 13 करोड़ रुपए थी। यानी करीब 9 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। बीयर को बाजार में खपाने का मामला मुख्य सचिव अनुराग जैन के संज्ञान में भी आ गया है।

सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर से मप्र में एक्सपायर्ड शराब वापस आई। दरअसल, मप्र से सोम कंपनी की हंटर बीयर 50 ट्रक भरकर छत्तीसगढ़ भेजी गई थी। कुल 55,090 पेटी बीयर एक्सपायर होने से इसे सितंबर 2024 में मप्र वापस भेज दिया गया। 4 महीने बाद, 21 जनवरी 2025 को आबकारी विभाग ने सुबह साढ़े दस बजे इसका नष्टीकरण करने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक, रायसेन सेहतगंज स्थित सोम डिस्टलरी कंपनी ने इस एक्सपायर्ड बियर को अपने आउटलेट्स और दुकानों से ग्राहकों को बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को छुपाने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिलकर एक फर्जी नष्टीकरण दिखा दिया। सूत्रों के अनुसार डेढ़ घंटे में साढ़े चार लाख लीटर शराब नष्ट करने का दावा किया गया, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। इतनी मात्रा में शराब के नष्टीकरण में भारी मात्रा में मजदूर लगने थे, जो नहीं लगाए गए। लेकिन वीडियो ग्राफी में कुछ ही पेटी पर बुलडोजर चलाया गया था।

विधानसभा में गूंजेगा मुद्दा

कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने विधानसभा में कथित शराब घोटाले को लेकर सवाल लगाया है। उन्होंने दावा किया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों और एक शराब कंपनी के बीच सांठगांठ कर बड़े पैमाने पर यह घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी मात्रा में शराब की गड़बड़ी हुई है। इस मुद्दे को हम विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। हीरालाल अलावा ने आगे कहा कि यह एक्सपायर्ड शराब थी, जिसे जहरीली भी कहा जा सकता है। उन्होंने आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को अमानक और एक्सपायर्ड शराब बेच दी गई, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। अब हम विभाग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और आगे कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे।

बिना अनुमति वापस आई बीयर

छत्तीसगढ़ से मप्र बीयर लाने के लिए आबकारी आयुक्त से पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई और यहां शराब दुकानों से बीयर विक्रय कर दी गई। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि यह नष्टीकरण सेहतगंज, जिला रायसेन स्थित सोम डिस्टलरी के प्लांट में किया गया। लेकिन पड़ताल में पता चला कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब स्टोर करने की वहां जगह ही नहीं थी, जिससे यह साफ होता है कि नष्टीकरण केवल कागजों पर किया गया। पहली दृष्टि में यह स्पष्ट है कि बिना प्रशासनिक मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपयर्ड शराब की खेप राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती थी। खासकर जब यह खेप छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश के रायसेन तक पहुंची, तब रास्ते में आबकारी विभाग और पुलिस की चुप्पी संदेह पैदा करती है। एक्सपायर्ड बीयर का इस तरह से लाया जाना यह दर्शाता है कि न केवल कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया गया। यह स्थिति बताती है कि शराब व्यापार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसमें न केवल स्थानीय अधिकारी, बल्कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस घोटाले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इतनी बड़ी खेप की जानकारी आबकारी कमिश्नर को नहीं थी या फिर इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।

निशाने पर पूरा विभाग...

बीयर को बाजार में खपाने का मामला मुख्य सचिव अनुराग जैन के संज्ञान में भी आ गया है। सूत्रों का कहना है कि मामले में आबकारी आयुक्त की भूमिका को लेकर नोटिस जारी किया जा सकता है। वहीं आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि बिना अनुमति छत्तीसगढ़ से शराब की पेटियां वापस लाने पर रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था, पर वह बीयर के नष्टीकरण की प्रक्रिया पर मौन साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित ने इस बीयर के नष्टीकरण की अनुमति मांगी थी जो दी गई थी। इधर, रायसेन की सहायक आबकारी उपायुक्त वंदना पांडे का कहना है कि वह आयुक्त की अनुमति के बिना मीडिया से बातचीत नहीं करेंगी। आबकारी एक्ट में निर्यात बीयर वापस आने का कोई प्रविधान नहीं है। वापस निर्यात की गई बीयर सोम डिस्टलरी में किसकी सक्षम अनुमति से प्राप्त की गई, या तस्करी करके लाई गई? भाड़ा किसने दिया? वाहन कौन से थे, बिना अनुमति बड़ी संख्या में बीयर डिस्टलरी के अंदर प्रवेश कैसे करवा दी गई? यह तमाम सवाल आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं। आबकारी विभाग ने प्रेस नोट में नष्टीकरण की गई बीयर की कीमत चार करोड़ 20 लाख के लगभग बताई। जबकि वास्तविक कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक है। सोम की हंटर ब्रांड बियर की मार्केट वैल्यू 220 रुपये प्रति बोतल के करीब है। यदि औसत एक बोतल की कीमत 200 रुपये भी मान ली जाए तो एक पेटी में 12 गुणित 200= 2400 रुपये इस तरह 55090 पेटी शराब की कीमत 55090 गुणित 2400 बराबर 13.22 करोड़ रुपये से अधिक होती है। विभाग ने जानबूझकर नष्टीकरण की गई बियर की कीमत को आधे से भी कम दिखाया।

एक्सपायर्ड बीयर हो सकती है खतरनाक, बिगड़ सकता है स्वास्थ्य

एक्सपायर्ड शराब या बीयर पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, चिकित्सकों के मुताबिक एक्सपायर्ड शराब पीने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, सिरदर्द और पेट में जलन। समय के साथ इनमें बैक्टीरिया या फंगस विकसित हो सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपायर्ड बीयर का कार्बोनेशन कम हो जाता है, जिससे इसका स्वाद और गंध बिगड़ सकती है, जबकि शराब में ऑक्सीडेशन के कारण उसका असर और गुणवत्ता बदल सकती है। हालांकि अत्यधिक पुरानी शराब टॉक्सिक हो सकती है। बीयर या शराब पीने के दौरान लोग कई बातों का खयाल नहीं रखते हैं। किसी भी पार्टी के लिए वाइन शॉप पर जाते हैं और बीयर की पेटी उठा लेते हैं। इसके बाद तुरंत घर पर आकर इसे पीने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये बीयर आपकी पार्टी को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। अगर आपने बीयर पर लिखी एक चीज को ठीक से नहीं देखा तो ये छोटी सी भूल आपको महंगी पड़ सकती है। दरअसल कई लोग बीयर पर बिना एक्सपायरी डेट देखे ही इसे पी लेते हैं। कई लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं होती है कि बीयर की बोतल पर भी एक्सपायरी डेट होती है। कुछ जगहों पर विक्रेता अपना स्टॉक खत्म करने के लिए पुरानी बीयर बेचते हैं, जिसे पीना आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है एक्सपायरी डेट वाली बीयर बेचने के लिए शराब विक्रेता कई आकर्षक ऑफर भी देते हैं। इसीलिए अगर आपको कम पैसों में या फिर एक के साथ एक फ्री बीयर मिल रही है तो इसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें, अगर बीयर एक्सपायर हो चुकी है तो उसे बिल्कुल न लें और इसकी शिकायत भी करें। दरअसल बीयर में अल्कोहल की मात्रा 4 से 8 प्रतिशत तक होती है। बाकी हिस्से में जौ और अन्य तरह का पानी होता है। ऐसे में शराब के मुकाबले ये जल्दी एक्सपायर हो जाती है। आमतौर पर बीयर 6 महीने में एक्सपायर हो जाती है। इसीलिए इसे 6 महीने के भीतर ही पी लेना चाहिए। अगर आपने बीयर खोल दी है तो उसे तुरंत पी लें, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। साथ ही खुली बीयर में बैक्टीरिया आदि का खतरा भी हो सकता है।

जेबों की सर्जरी

यह खबर परेशान करती है कि देश के करोड़ों मरीज पहुंच से बाहर के महंगे इलाज के कारण गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। वे कथित रुप से दूसरे भगवान कहे जाने वाले शख्स के आगे बेबस नजर आते हैं। खासकर बड़े आप्रेशनों व उपकरणों से लेकर महंगी दवाओं को लेकर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मरीजों की दुखती रग को समझते हुए केंद्र व राज्य सरकारों से निजी अस्पतालों में मरीजों का शोषण रोकने के लिये नीतिगत फैसला लेने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि देशवासियों को चिकित्सा का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना राज्यों का कर्तव्य है। निर्विवाद रूप से राज्य सरकारें ऐसा करने में विफल रही हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने बड़े अस्पतालों को जमीन आदि तमाम सुविधाएं रियायती दरों पर दी हैं। ऐसे में वे गरीब मरीजों को राहतकारी इलाज देने के लिये बड़े अस्पतालों को बाध्य कर सकती थीं। वैसे चुनावों के दौरान तमाम तरह के सब्जबाग दिखाने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे में चिकित्सा सुविधा सुधार कभी प्राथमिकता नहीं रही। यदि सार्वजनिक चिकित्सा का बेहतर ढांचा उपलब्ध होता तो लोग निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर न होते। यदि निगरानी तंत्र मजबूत होता और प्रभावी कानून होते तो मरीजों को दोहन का शिकार न होना पड़ता। यदि मरीजों से निजी अस्पतालों में मनमानी रकम वसूली जाती है तो यह राज्य सरकारों की छवि पर आंच है कि वे मरीजों को किफायती उपचार उपलब्ध कराने में विफल रही हैं। यही वजह है कि शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि मरीजों को उचित मूल्य वाली दवाइयां न मिल पाना राज्य सरकारों की नाकामी को ही दर्शाता है। इतना ही नहीं राज्य सरकारें निजी अस्पतालों को न केवल सुविधाएं प्रदान करती हैं बल्कि उन्हें प्रोत्साहन भी देती हैं। सरकारों का यह दावा अतार्किक है कि मरीजों के तिमारदारों के लिये निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोरों से दवा खरीदने की बाध्यता नहीं है।

दरअसल, अस्पताल की फार्मेसी या खास मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदना तिमारदारों की मजबूरी बन जाती है। उन्हें खास ब्रांड की दवा व उपकरण खरीदने के निर्देश होते हैं। दरअसल, खुले बाजार में उनकी उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर आशंका होती है। असल में, यह नीति-नियंताओं की जवाबदेही है कि वे मरीजों और उनके परिवारों को शोषण से बचाने के लिये दिशा-निर्देश तैयार करें। हालांकि, यह इतना भी आसान नहीं है क्योंकि विभिन्न हितधारकों के दबाव अकसर सामने आते हैं। जैसा कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को उस समय कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था जब उसने डॉक्टरों से कहा था कि वे ब्रांडेड दवाएं न लिखें। उसके स्थान पर जेनेरिक दवाएं लिखें, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा बिरादरी ने तब दबाव बनाते हुए कहा था कि दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जिसके बाद यह आदेश जल्दी ही वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा ब्रांडेड दवाओं के निर्माताओं ने भी दबाव बनाया था, जो कि जन-कल्याण के बजाय बड़े पैमाने पर मुनाफे को प्राथमिकता देते रहते हैं। वैसे निजी अस्पतालों द्वारा दवाओं के जरिये पैसा कमाने की वजह यह भी है कि सरकारी जन-औषधि केंद्रों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ये केंद्र, जिनकी देश में संख्या पंद्रह हजार के करीब है, देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। ये केंद्र नागरिकों को सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिये बनाये गए थे। लेकिन, ये केंद्र दवाओं की कमी,गुणवत्ता के नियंत्रण के अभाव और ब्रांडेड दवाओं की अनधिकृत बिक्री की समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। निश्चित रूप से औषधि विनियामक प्रणाली में सुधार करने से तमाम असहाय रोगियों की परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है। एक रिपोर्ट बताती है कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों का खर्च सात गुना होता है। खासकर कोरोना काल के बाद चिकित्सा खर्च में खासी बढ़ोतरी हुई है। निस्संदेह, राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार कर उचित गाइडलाइंस बनानी चाहिए। निजी अस्पतालों व मरीजों के हितों के मद्देनजर राज्य सरकारों के संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

विचार बीज है और प्रचार बीजों का अप्राकृतिक विस्तार!

अनिल त्रिवेदी

“विचार और प्रचार दोनों के बीच अन्तर्सम्बन्धों पर जब हम सोचते विचारते है तो यह सूत्र मिलता है कि विचार ही प्रचार का जन्मदाता है। विचार मूलतः चिन्तन प्रक्रिया का मूल या बीज ही माना जाएगा। यदि विचार न हो तो चिन्तन, मनन, लेखन और सृजन या विध्वंस कुछ भी उत्पन्न हो ही नहीं सकता। शून्य के विचार में शून्यता के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। शून्य में यदि कुछ भी अस्तित्व है तो वह शून्य तो नहीं शून्य से अलग कुछ और हो सकता है। विचार अस्तित्व है तो शून्य अस्तित्व का अभाव है। अस्तित्व साकार या सगुण हैं तो शून्य निराकार निर्गुण हैं।रेखा गणित में बिन्दु की जो परिभाषा मानी गई है कि जिसमें न तो लंबाई हो और न चौड़ाई उसे बिन्दु माना गया है।याने एक तरह से बिंदु काल्पनिक है क्योंकि बिन्दु की रेखागणितीय परिभाषा में कल्पना की गयी है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई न हो वह बिन्दु है।इस मान्यता पर ही समूची रेखागणितीय अवधारणाएं अस्तित्व में आई और मस्तिष्क में निराकार विचार विमर्श या चिंतन परम्परा का उदय हुआ या इसे यों भी कहा जा सकता है कि मान कर सोचने विचारने का एक विचार जन्मा। विचार कुछ भी कहीं भी कैसे भी अचानक और सोचने समझने और समझाने के दौरान उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते या शांत भाव से बैठे ठाले भी आ सकता है। विचार बातचीत या बोलने चालने और मिलने जुलने पर भी आ सकते हैं।कई बार बहुत सोचने पर भी विचार नहीं आते या आते हैं तो उनमें कोई सार नहीं होता फिर भी मनुष्य के मन मस्तिष्क में विचार की अंतहीन हलचलों का सिलसिला जारी रहता है।”

विचार यात्रा में मनुष्य को यह विचार आया कि विचारों को अपने आप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। विचारों को फैलाना चाहिए इसी क्रम में प्रचार के विचार का जन्म हुआ। इस तरह हम मान सकते हैं कि प्रचार भी विचार का किसी निश्चित हेतु की दृष्टि से किया गया विस्तार ही है। विचार को प्रचारित करने के विचार ने मनुष्य समाज की चिन्तन प्रक्रिया को ही बदल डाला है और आज के कालखंड में प्रचार को लेकर नये नये प्रयोग करने का एक शास्त्र या मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रचार तंत्र के माध्यम से अपने अधीन कर ने का प्रचार साम्राज्य तो स्थापित हो चुका है।आज की दुनिया विचार से ज्यादा प्रचार की बावली होती प्रतीत हो रही है।आज सूचना प्रौद्योगिकी के काल खंड में मानव समाज में मौलिक विचार प्रक्रिया पर निर्भरता क्षीण होते जाने के साथ साथ प्रचार की अंतहीन भूख बढ़ती ही जा रही है।इस तरह प्रचार का अंतहीन सिलसिला सुनामी की तरह मनुष्य समाज की विचार प्रक्रिया को ही एक तरह से कुंद कर रहा है।

प्रचार के कृत्रिम साम्राज्य के अधीन मानव सभ्यता और समाज के सोच विचार और आपसी व्यवहार में अत्यधिक महत्वपूर्ण बदलाव आते दिखाई देते हैं। प्रचार तंत्र के अंतहीन विस्तार ने मानव संकल्पनाओं और दैनिक जीवन के आपसी व्यवहार और आचरण को ही पूरी तरह बदल डाला है। विचार मनुष्य की प्राकृतिक शक्ति है पर प्रचार के लिए अप्राकृतिक संसाधन और आर्थिक, राजनैतिक, व्यापारिक और तकनीकी संस्थानों की शक्तियों का सहयोग और ऐजेण्डा चाहिए। अकेला मनुष्य अपने बल बूते विचार कर सकता है पर प्रचार अकेले बिना संसाधनों के संभव नहीं है।आज की दुनिया को यह लगने लगा है कि बिना प्राकृतिक विचारों के भी हम जी सकते हैं पर बिना प्रचार के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक, राजनैतिक, व्यापारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक या निजी और सार्वजनिक गतिविधियों को बिना प्रचार के सफलता के साथ सम्पन्न करना संभव ही नहीं है यह चिन्तन प्रक्रिया तेजी से फैलतीं हुई दिखाई पड़ती हैं और आधुनिक काल के मनुष्य अपनी वैचारिक तेजस्विता के बजाय आभासी प्रचार तंत्र को आसान जीवन का पर्याय मानने की दिशा पकड़ते दृष्टिगत हो रहे हैं।

आज के कालखंड में प्राकृतिक जीवन श्रृंखला के बजाय आभासी अप्राकृतिक संसाधनों की बाढ़ मानव बसाहटों में मानव सभ्यता का आवश्यक हिस्सा बनती जा रही है। विचार विमर्श सहित लेखन चिंतन और सृजनात्मक शक्तियों जैसे प्राकृतिक मानवीय गुण अब अप्राकृतिक संसाधनों या शक्तियों के विशेष अधिकार सामान्यतः बनते जा रहे हैं।हमारा समूचा मानव जीवन अप्राकृतिक विस्तार पर निर्भर होता जा रहा है। राज्य, समाज और बाजार तीनों मनुष्यों को सृजनात्मक शक्ति का वाहक बना कर चैतन्य नागरिकों का समाज खडा करने की दिशा में बढ़ने के बजाय यंत्र आधारित अप्राकृतिक प्रज्ञा आधारित मनुष्य सभ्यता की दिशा में बढ़ते हुए मानवीय सभ्यता की विविधता को विलुप्त करने की दिशा में अग्रसर होने को ही विकसित सभ्यता का पर्याय बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क में प्राकृतिक विचार और व्यवहार क्षीण हो कर अप्राकृतिक यंत्रों से चलने वाली दुनिया में मनुष्य यंत्रवत अप्राकृतिक संसाधनों के भरोसे जीने लगा है। मनुष्य जीवन को प्रकृति प्रदत्त वाणी, ज्ञानेंद्रियों और विचार विमर्श से ओतप्रोत चैतन्य नागरिक बनने के बजाय अप्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित राज्य, समाज और बाजार का अदना उपभोक्ता बनता जा रहा है। आधुनिक दुनिया को अप्राकृतिक संसाधनों का अजायबघर जैसा बना रहा है। इस तरह सनातन समय से चली आ रही जीवन्त प्राकृतिक दुनिया को अप्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित,जीवनी शक्ति विहीन उपभोक्ताओं का जीवन मानों एक बड़े कठपुतली के खेल में बदल रहा है।आज मानव समाज विचार की नैसर्गिक और जीवन्त दिशा को त्याग एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलने वाली प्रचार साम्राज्य की आधुनिक दुनिया में मानव जीवन को बदलने की निरंतर कोशिश कर रहा है। मनुष्य जीवन का प्राकृतिक सनातन जीवन्त स्वरूप है। मनुष्य अप्राकृतिक संसाधनों पर जीने वाला यंत्र मानव नहीं है। प्रकृति प्रदत्त जीवन प्रचार से नहीं प्राकृतिक विचार श्रृंखला से ही सनातन काल से चलता आया है और चलता रहेगा। अप्राकृतिक प्रचार साम्राज्य मनुष्य के प्राकृतिक विचार बीज को अप्राकृतिक संसाधनों से समाप्त नहीं कर सकता यही मनुष्य के विचार की मूल आधारभूमि है। विचार का अंतहीन प्रवाह और उससे निकलने वाली वैचारिक हलचलों ने मनुष्य के वैचारिक स्वरूप को मौलिक रूप से बदल डाला है। विचार विमर्श और वैचारिक मतभेद ने मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति और वैचारिक ऊर्जा को नित नये आयाम प्रदान किए हैं जिनमें आधुनिक सभ्यता की अंतहीन उथल-पुथल समायी हुई हैं। विचार हीनता और विचार शून्यता एक तरह से मनुष्य की वैचारिकी के दो परस्पर विरोधी ध्रुव की तरह ही है। विचारों की अति और और विचारों की जटिलता मानवीय मन की अनंत गहराई और एक दम सरलता और सहजता सबको एक साथ अपने अंदर समाहित कर लेता है यह मानवीय प्रज्ञा की अनोखी विशेषता है। विचार प्राकृतिक स्वरूप में ओस की बूंद की तरह ही मन मस्तिष्क में आता है और सूर्योदय के बाद धूप की प्रखरता बढ़ने के साथ ही अपने आप अदृश्य हो सृष्टि में समाहित हो जाता है। वैसे ही विचार का प्राकृतिक स्वरूप असंख्य मस्तिष्कों में समाहित होते ही अपने मूल स्वरूप स्वभाव और प्राकृतिक स्वरूप को ओस की बूंद की तरह ही सृष्टि में समाहित कर लेता है।

लेखक अभिभाषक एवं स्वतंत्र है।
त्रिवेदी परिसर 304/2 भोलाराम उस्ताद मार्ग ग्राम पिपल्या राव आगरा मुम्बई राजमार्ग इन्दौर मध्यप्रदेश। मोबाइल 9329947486

टल गया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

अप्रैल में ऐलान संभव

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आरएसएस की बैठक के चलते देरी, महिला भी संभाल सकती है कमान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में और देरी हो सकती है। पहले कहा जा रहा था कि होली से पहले भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि अप्रैल तक यह मामला टल सकता है। यानी पार्टी को नया अध्यक्ष अप्रैल में ही मिलेगा। कहा जा रहा है कि राज्यों में हो रहे संगठन चुनावों में देरी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है लेकिन अभी तक 12 राज्यों में ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो पाया है।

पद के लिए और कौन-कौन हैं दावेदार?

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम भी चर्चाओं में हैं।धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े भी संभावित उम्मीदवारों में से हैं।इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और संगठन महासचिव बीएल संतोष को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। बंसल को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है।

आरआरएस की बैठक में उठेगा अध्यक्ष का मुद्दा

आरआरएस की बैठक में बीजेपी की तरफ से सुझाए नामों पर भी चर्चा होगी। ये भी तय होगा कि आरआरएस अपनी सलाह पर ही कायम रहेगा या पार्टी के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेगा। आरआरएस की बैठक में प्रांत स्तर के 1,480 पदाधिकारी शामिल होंगे। आरआरएस का शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष पद का नाम उनके सामने रखेगा।सोर्स के मुताबिक, आरआरएस ने अभी दो सलाह दी हैं, पहली पर पार्टी ने साफ तौर पर असहमति जता दी है, दूसरी पर स्थिति साफ नहीं है।

अध्यक्ष पद पर आरआरएस ऐसा चेहरा चाहता है, जिसका बैकग्राउंड संगठन का हो और वो संगठन का भरोसेमंद भी हो। वो अहम फैसलों में आरआरएस की राय को पार्टी के बराबर तरजीह दे।बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा ही कोई नाम चाहिए। उधर, आरआरएस को कोई ऐसा चाहिए, जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नीयत आरआरएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो।इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। यानी 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम सामने आना मुश्किल है।

सहमति क्यों नहीं बन पा रही?

सोर्स के मुताबिक, नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान में देरी की वजह आरआरएस और बीजेपी के बीच किसी एक नाम पर सहमति न बन पाना है। मंथन चल रहा है। बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा लीडर चाहिए। आरआरएस ऐसे चेहरे की तलाश में है, जो भरोसेमंद हो। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था, शुरू में हम कम सक्षम थे। तब हमें आरआरएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं। बीजेपी अब खुद को चलाती है। बीजेपी की लीडरशिप ने इस बयान का खंडन या निंदा नहीं की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी और संगठन के बीच दरार साफ दिखी। चाहे वो भागवत की स्पीच हो या फिर नड्डा का बयान। अब आरआरएस नहीं चाहता कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठे, जो संगठन से ऊपर पार्टी और उसकी लीडरशिप को तवज्जो दे।

गौरतलब है कि 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि राज्यों में संगठन चुनाव में देरी हो रही है। पिछले दिनों बिहार में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए लेकिन झारखंड में अभी चुनाव नहीं हुए हैं। भाजपा के संविधान के मुताबिक आधे राज्यों में चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, जबकि अभी तक सिर्फ 12 राज्यों में ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकी है। अभी कुछ और राज्यों में अगले दो हफ्ते में चुनाव होगा।उधर बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। इसमें आरएसएस के सभी पदाधिकारियों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी हिस्सा लेंगे। कुल डेढ़ हजार से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक के लिए आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी 17 मार्च से ही बेंगलुरु पहुंचने लगेंगे। इसलिए भाजपा के नेतृत्व को इंतजार करना होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी की 3 बड़ी वजह...

1. **राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी:** आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव में देरी। जरूरी है, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकी है। चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने और तारीख तय करने में ही 10-12 दिन लग सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें करीब 12-15 दिन का समय लगेगा।
2. **आरएसएस की बैठक में देरी से 24 मार्च तक अंतिम फैसला:** संभव बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी का एक कारण आरएसएस की बैठक भी है। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी 17 से 24 मार्च तक बेंगलुरु में रहेंगे, जिसके चलते बीजेपी नेतृत्व को नए अध्यक्ष पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 24 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है।
3. **हिंदू नववर्ष के पहले महीने यानि अप्रैल में ऐलान पर विचार:** बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को हिंदू अस्मिता से जोड़ना चाहती है। इसलिए माना जा रहा है कि 30 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष के बाद घोषणा हो सकती है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को जनवरी के बजाय हिंदू नववर्ष के पहले महीने यानि अप्रैल में कराने पर विचार कर रही है।

हिंदू नववर्ष का चुनाव से क्या कनेक्शन?

वैसे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी के लिए एक तर्क हिंदू नववर्ष का दिया जा रहा है। हिंदू नववर्ष की शुरूआत चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा से होती है, जो इस साल 30 मार्च को है। महाकुंभ में 64 करोड़ लोगों से स्नान को हिंदू अस्मिता के जागरण से जोड़कर भाजपा अपने नए अध्यक्ष के चुनाव को जनवरी के बजाय हिंदू नव वर्ष के पहले महीने के साथ जोड़ना चाहती है।

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य अध्यक्षों का ऐलान जल्द: भाजपा के संविधान के अनुसार, 50 प्रतिशत राज्यों में चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता।अब तक भाजपा ने 12 राज्यों में चुनाव पूरे कर लिए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी कर दिया है।भाजपा 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा।अगले 10-15 दिन में बचे राज्यों में चुनाव होने की खबरें हैं।

पहली बार कोई महिला बन सकती है अध्यक्ष: रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा किसी महिला के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। चर्चाएं हैं कि दक्षिण भारत से किसी महिला को यह जिम्मेदारी मिल सकती है।दावेदारों में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयंबटूर विधायक वनथी श्रीनिवासन और आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का नाम चर्चा में है। पुरंदेश्वरी 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थीं।वहीं, वनथी हाल ही में कई कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आई हैं।

भाजपा अध्यक्ष से जुड़ी ये बातें भी जानिए: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे जरूरी है कि नामांकन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो।प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और एक व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

केजरीवाल-सिसोदिया के बाद आतिशी, गोपाल राय निशाने पर!

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आप के दौर में हुए घोटालों की परतें खोलने की तैयारी में है। कुछ घोटाले पंजाब चुनाव के आसपास भी सामने लाए जाएंगे। इसमें से एक शिक्षा घोटाला भी हो सकता है।'दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है। ये शराब घोटाले के बराबर होगा। सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जब कैग की रिपोर्ट पेश होगी, तो बड़ी हेराफेरी सामने आएगी। मनीष सिसोदिया लिकर स्कैम में जेल गए थे, अब एजुकेशन स्कैम में जाएंगे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। उनके मुताबिक, आप सरकार के काम पर कैग की 2 से 3 रिपोर्ट ऐसी हैं जो जारी हुईं तो शराब घोटाले जैसे स्कैम सामने आएंगे। इसमें आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय फंस सकते हैं।

अब तक सामने आई कैग की दो रिपोर्ट्स

1. लिकर पॉलिसी और सप्लाई पर ऑडिट

दिल्ली की नई शराब नीति अब रद्द हो चुकी है। हालांकि, कैग की रिपोर्ट में इससे 2,002 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस का दावा किया गया है। रिपोर्ट में लाइसेंस देने में गड़बड़ी और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से तीन गड़बड़ियां सामने आईं।

1-गलत फैसलों की वजह से सरकार को यादा राजस्व का नुकसान हुआ। नॉन कंफर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोलने की वजह से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

2-छोड़े गए लाइसेंस को री-टेंडर नहीं करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना के नाम पर लाइसेंस फीस माफ करने के फैसले से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

3-सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट ना करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

14 कैग रिपोर्ट में पैसों की हेराफेरी

दिल्ली में 10 साल सरकार चलाने के बाद आप अब विपक्ष में है। बीजेपी सरकार आप सरकार के वक्त से पेंडिंग कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर रही है। कुल 14 रिपोर्ट हैं, जिनमें से लिकर पॉलिसी और हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं। लिकर पॉलिसी में 2002 करोड़ रुपए का नुकसान सामने आया है। वहीं, दूसरी रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इन्फ्राच्ट्रक्चर एंड सर्विस की है। इसमें कोरोना काल में फंड और उसके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपए जरूरत होने पर भी खर्च नहीं किए। बाकी बची 12 रिपोर्ट्स में क्या है, ये पेश हुईं तो आप के कौन से नेता फंस सकते हैं, उन पर किस तरह के आरोप लग सकते हैं और क्या कार्रवाई हो सकती है।

सदन में पहले सिर्फ एक रिपोर्ट आनी थी, सरकार दो रिपोर्ट ले आई

बीजेपी सोर्स बताते हैं, हमने पहले विधानसभा सत्र में सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करने का मन बनाया था। बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी जारी कर दी। इसका ये मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अब चैन की सांस ले सकते हैं। 12 रिपोर्ट अब भी लाइन में हैं। कुछ-कुछ समय पर ये जारी होती रहेंगी। पार्टी में हमारे दूसरे सोर्स बताते हैं, 12 में से 2-3 रिपोर्ट में आप सरकार पर गंभीर आरोप हैं। कई पूर्व मंत्री पहले से जांच के दायरे में हैं। वे नए मामलों में भी फंस सकते हैं। पार्टी के कुछ और पूर्व मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग सकते हैं।

शराब घोटाले से बड़े एजुकेशन स्कैम का दावा

एजुकेशन डिपार्टमेंट

'ऑडिट में मिलेगा बड़ा घोटाला, आप को सबसे बड़ा झटका लगेगा'

सोर्स के मुताबिक, शराब घोटाले के बाद अगर आप सरकार का दूसरा बड़ा घोटाला सामने आएगा, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा। नई सरकार ने जिन 14 रिपोर्ट्स का जिक्र किया था, उसमें शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, टीचर्स की भर्ती और एजुकेशन पॉलिसीज में बजट के इस्तेमाल की समीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं।ये रिपोर्ट अभी सदन में क्यों पेश नहीं की? सोर्स जवाब देते हैं, सारे झटके एक साथ नहीं देंगे। अभी तो 5 साल बाकी हैं। सही समय देखकर जनता के सामने शिक्षा विभाग की रिपोर्ट रखी जाएगी।

सोशल सेक्टर की योजनाएं

मुफ्त बिजली-पानी और ऐसी ही बाकी योजनाओं के कामकाज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट इसमें आती है। सदन में पेश की जाने वाली ये तीसरे नंबर की रिपोर्ट हो सकती है। इसमें एससी-एसटी कम्युनिटी के लिए चलाई जा रही योजनाओं में खर्च होने वाला फंड सवालों के घेरे में है।हर साल आम आदमी पार्टी की सरकार में इस कम्युनिटी के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया जाता था। सोर्स के मुताबिक, कम्युनिटी पर इस रकम का बहुत मामूली हिस्सा खर्च होता था। बाकी बचा फंड दूसरे विभाग में ट्रांसफर होता था। कैग की रिपोर्ट में फंड की हेराफेरी का मामला सामने आएगा।

मुख्यमंत्री आवास का रेनोवेशन

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये मूल बजट 7.61 करोड़ रुपए से 5 गुना ज्यादा था। इस रिपोर्ट में बजट से ज्यादा खर्च और ट्रांसपेरेंसी की कमी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि, अभी ये रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई है। बीजेपी सीएम हाउस को शीशमहल बताकर इस पर हुए खर्च का डेटा टुकड़ों-टुकड़ों में जारी करती रही है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्द भी बना था।

पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जांच के दायरे में आएंगे

राजेंद्र पाल गौतम 14 फरवरी 2015 से 19 अक्टूबर 2022 तक समाज कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग के मंत्री रहे। 3 नवंबर 2022 से 11 अप्रैल 2024 तक राजकुमार आनंद ने ये मंत्रालय संभाला। सोर्स के मुताबिक फंड की हेराफेरी के मामले 2023 से पहले के हैं। अगर इसकी रिपोर्ट सामने आई, तो जांच के दायरे में राजेंद्र पाल गौतम ही आएंगे।

पॉल्यूशन पर किए खर्च का ऑडिट

पॉल्यूशन के अलावा बाकी कामों जैसे कचरा प्रबंधन में सरकार के काम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आएगी। पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, इस रिपोर्ट में इसकी भी जांच की गई है। ये कैग की शुरुआती 5 रिपोर्ट में शामिल है। इमरान हुसैन 14 फरवरी 2015 से 14 फरवरी 2020 तक पर्यावरण मंत्री रहे। फिर 16 फरवरी 2020 से 17 सितंबर 2024 तक ये विभाग गोपाल राय के पास रहा। गड़बड़ी सामने आने पर ये दोनों मंत्री जांच के दायरे में आ सकते हैं।

पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज

हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी कैग की 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्रर की कमी है। नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं के हेल्थ प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है। एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं हैं। आईसीयू की कमी है।मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ पॉलिसीज के लिए आए फंड के इस्तेमाल और खर्च की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के फंड और मैनेजमेंट पर सवाल उठाए गए हैं। सबसे यादा सवाल मोहल्ला क्लिनिक के मैनेजमेंट पर उठे हैं।रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं हैं। अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी थी, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया।रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र से 787.91 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च हुए।कैग रिपोर्ट के मुताबिक, हेल्थ वर्कर्स की भर्ती और सैलरी के लिए 52 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से 30.52 करोड़ खर्च ही नहीं किए गए। यानी महामारी के दौरान लोग मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे थे। उस वक्त में भी दिल्ली सरकार ने स्टाफ की भर्ती नहीं की।इसी तरह दवाओं, पीपीई किट और अन्य मेडिकल सप्लाई के लिए मिले 119.85 करोड़ में से 83.14 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए।

जांच के दायरे में आएंगे सिसोदिया और आतिशी

जेल जाने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 14 फरवरी 2015 से 28 फरवरी 2023 तक दो कार्यकाल में सिसोदिया ने ये विभाग संभाला। अब शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया पर दूसरी मुसीबत शिक्षा घोटाले से आ सकती है।दिल्ली सरकार आप के दौर में हुए घोटालों की परतें खोलने की तैयारी में है। कुछ घोटाले पंजाब चुनाव के आसपास भी सामने लाए जाएंगे। इसमें से एक शिक्षा घोटाला भी हो सकता है।आतिशी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संभाला था। उन्हें काम करने के लिए 2 साल से भी कम वक्त मिला। उन पर भी आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन मुख्य आरोपी सिसोदिया ही रहेंगे। सोर्स ने बताया, जिस एजुकेशन मॉडल पर केजरीवाल ने इंटरनेशनल अवॉर्ड बटोरे, आप सरकार ने पूरे देश में जिस मॉडल का प्रचार किया और वाहवाही लूटी, ये रिपोर्ट उसे बिल्कुल खत्म कर देगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की कैग रिपोर्ट आप के लिए बड़ा झटका लेकर आएगी।

पूर्व श्रम मंत्री गोपाल राय आ सकते हैं जांच के दायरे में

लेबर डिपार्टमेंट का काम भले ही कैग की 14 रिपोर्ट्स में शामिल नहीं है, लेकिन इस विभाग की गड़बड़ियों पर भी नई सरकार की नजर है। सोर्स के मुताबिक, ये विभाग जांच के दायरे में है। भविष्य में लेबर डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन सकता है। 14 फरवरी 2015 से 14 फरवरी 2020 तक गोपाल राय दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री रहे। उसके बाद 16 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2023 तक सत्येंद्र जैन ने ये विभाग संभाला। सोर्स के मुताबिक, इस विभाग में फंड की हेराफेरी या घोटाले से यादा फंड खर्च न करने का मामला सामने आ सकता है।आरोप है कि इस विभाग के लिए फंड दिया जाता था, लेकिन फंड खर्च करने की जगह उसे फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाता था। फिर उससे आने वाले ब्याज का इस्तेमाल पार्टी अपने खर्चों के लिए करती थी।ये रकम 3 हजार करोड़ रुपए से यादा है। इस पर अगर 2.5त्न ब्याज भी जोड़ा जाए, तो ये 75 करोड़ रुपए होता है। इसे लगातार पार्टी के खर्च में इस्तेमाल किया गया। इसकी रिपोर्ट पेश हुई, तो गोपाल राय और सत्येंद्र जैन जांच के दायरे में आएंगे।

कैसे हुआ 2002 करोड़ का शराब घाटा?

पेज-8 पर

शराब घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को पेश किया। इसे विधानसभा के सदन में रखे जाने के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। कैग रिपोर्ट में जिस बात पर भाजपा नेताओं ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, वह है 2002 करोड़ रुपये का घाटा, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर दिल्ली शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट में क्या-क्या है? इसमें आखिर किस तरह से 2002 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया है? कैग ने किस-किस क्षेत्र में सरकार की तरफ से चूक की बात कही है? इसके अलावा इसके क्या कारण बताए हैं?

कैसे हुआ 2002 करोड़ का शराब घोटाला?

दिल्ली शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट, नई शराब नीति में कहां-कहां हुई गलतियां?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-2022 की आबकारी नीति से 2002 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ। अब समाप्त हो चुकी शराब नीति के निर्माण में बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया था। रिपोर्ट में 941.53 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान का दावा है। इसके अलावा गैर-अनुरूप नगरपालिका वार्ड में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई। लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। लाइसेंसधारियों को अनियमित अनुदान छूट के कारण 144 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। इस लिहाज से कुल-मिलाकर आप सरकार की तरफ से लाई गई शराब नीति से दिल्ली को 2029 करोड़ का घाटा हुआ।

हेल्थ डिपार्टमेंट पर CAG रिपोर्ट

क्या गड़बड़ियां मिलीं

- कोविड के दौरान **AAP सरकार** ने केंद्र से मिले 787.91 करोड़ रुपए फंड में से सिर्फ **582.84 करोड़** रुपए इस्तेमाल किए
- PPE किट, मास्क और दवाओं के लिए जारी **119.85 करोड़** रुपए में से **83.14 करोड़** रुपए इस्तेमाल नहीं हुआ

- **21 मोहल्ला क्लिनिकों** में टॉयलेट नहीं, **15** में बिजली और **6** में टेबल का इंतजाम नहीं था
- **49** आयुष डिस्पेंसरी में से **17** में बिजली, **7** में टॉयलेट और **14** में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी

- दिल्ली सरकार ने **2016-17** से **2020-2021** तक के बजट में अस्पतालों में कुल **32 हजार बेड** बढ़ाने का वादा किया, लेकिन सिर्फ **1357 बेड** बढ़ाए
- **AAP सरकार** के कार्यकाल में सिर्फ तीन नए अस्पताल बने, इसमें तीसरे अस्पताल की लागत टेंडर की लागत से बहुत ज्यादा थी
- दिल्ली के **27** अस्पतालों में से **14 में ICU, 16** में ब्लड बैंक, **8** में ऑक्सीजन, **15** में मॉर्च्युरी और **12** में एम्बुलेंस नहीं थी

1. दिल्ली को 941 करोड़ रुपये का नुकसान कैस हुआ?

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के तहत गैर-अनुरूपित क्षेत्रों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नगर निगम (एमसीडी) से स्वीकृति नहीं ली गई थी। दरअसल, दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी-2021) के मुताबिक, मिश्रित भूमि उपयोग और गैर-अनुरूपित क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना प्रतिबंधित था और इसके लिए डीडीए-एमसीडी की मंजूरी अनिवार्य थी। हालांकि, आबकारी विभाग ने इस प्रतिबंध के बावजूद 67 गैर-अनुरूपित वॉर्डों में दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। 16 नवंबर 2021 को डीडीए ने इन दुकानों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और इन्हें बंद करने का निर्देश दिया। इसके चलते लाइसेंसधारक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। 9 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार इन दुकानों से लाइसेंस शुल्क नहीं वसूल सकती। इसके चलते कुल 941 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ।

2. दिल्ली के शराब घोटाले में 890 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ?

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के तहत 19 जोनल लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं ने अपने लाइसेंस नीति की समाप्ति से पहले ही सरेंडर कर दिए थे। मार्च 2022 में 4 जोन, मई 2022 में 5 जोन और जुलाई 2022 में 10 जोन के लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस वापस कर दिए थे। हालांकि, आबकारी विभाग ने इन जोन के लिए फिर से नीलामी (री-टेंडरिंग) नहीं की, जिससे सरकार को 890 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। इन जोन में शराब की दुकानों के संचालन के लिए कोई वैकल्पिक योजना भी नहीं बनाई गई, जिससे इन क्षेत्रों में शराब की खुदरा बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई। सरकार को नियम के तहत इन जोन की नई नीलामी करनी थी, ताकि इनका संचालन जारी रह सके। हालांकि, ऐसा न होने के कारण इन जोन्स से कोई भी आबकारी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ, जिससे यह भारी नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई शर्त नहीं थी कि अगर कोई लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस छोड़ता है।

3. शराब घोटाले में 144 करोड़ रुपये के नुकसान की वजह क्या?

कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब की दुकानें बंद रही थीं। लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस फीस में छूट की मांग की। दिल्ली के आबकारी और वित्त विभाग ने इस छूट का विरोध किया, क्योंकि टेंडर दस्तावेजों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी ही नहीं। सभी व्यावसायिक जोखिम लाइसेंस धारकों पर ही लागू होने चाहिए थे। 6 जनवरी 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को आदेश दिया कि वह इस विषय पर एक स्पष्ट और तार्किक निर्णय ले। इसके बाद आबकारी विभाग ने स्पष्ट कहा कि शराब की बिक्री में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई है, इसलिए कोविड प्रतिबंधों के कारण छूट देना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह छूट लाइसेंसधारकों को दे दी। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी किसी छूट के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेना अनिवार्य था, लेकिन यह फैसला मंत्री-प्रभारी के स्तर पर ही ले लिया गया।

शराब की क्वालिटी परखने पर नहीं दिया गया ध्यान

इतना ही नहीं दिल्ली की नई शराब नीति के तहत शराब की गुणवत्ता परीक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं बनाई गई। सरकार ने शराब परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, इसे जमीन पर लागू नहीं किया गया। इसके अलावा शराब के बैचेज के परीक्षण और ब्रांड प्रमोशन पर निगरानी तंत्र भी लागू नहीं लागू किया। विभाग ने अवैध व्यापार और ब्रांड धांधली की शिकायतों की सही से जांच नहीं की। ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा।

दिल्ली शराब नीति से 27 करोड़ रुपये का नुकसान कैसे हुआ?

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के तहत जोनल लाइसेंस धारकों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट की गलत गणना की गई। दरअसल, शराब लाइसेंसधारकों को अपनी सालाना लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा कराना होता है। यानी एक साल के लाइसेंस के लिए जितनी भी फीस लगनी होती है, उसकी करीब एक-चौथाई फीस सिक्योरिटी में दी जाती है। इसकी वजह यह है कि अगर लाइसेंसधारक फीस भुगतान में चूक करता है और एक महीने में अपना भुगतान नहीं कर पाता, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और सरकार को भुगतान न मिलने पर यह सिक्योरिटी डिपॉजिट सुरक्षा कवर का काम करता है। चूंकि दिल्ली सरकार की शराब नीति नवंबर में लागू हुई थी, इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 में शराब नीति सिर्फ साढ़े चार महीने के लिए ही प्रभावी रही। इसके चलते आबकारी विभाग ने वार्षिक लाइसेंस शुल्क की जगह प्रो-राटा लाइसेंस शुल्क के 25% के आधार पर जमा राशि तय की, जिससे लाइसेंस धारकों को करीब एक महीने की ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ी। इस नीति के चलते जब जोन-8 के लाइसेंसधारक ने मार्च 2022 में संचालन बंद कर दिया तो उन पर 47.46 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 30 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा थी। इसी तरह जोन-30 के लाइसेंसधारक ने जुलाई 2022 में संचालन बंद कर दिया, लेकिन 9.82 करोड़ रुपये का बकाया रह गया। इन दो जोन्स में ही लाइसेंसधारकों से कुल 27 करोड़ रुपये की राशि वसूल नहीं हो पाई, जिससे सरकार को सीधा नुकसान हुआ।

केजरीवाल सरकार की 14 पेंडिंग CAG रिपोर्ट्स

- स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट (मार्च 2021)
- रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल-जनरल सेक्टर और PSU रिपोर्ट (31 मार्च 2020 से 2021)
- दिल्ली में पॉल्यूशन की रोकथाम की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च 2021)
- जरूरतमंद बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च 2021)
- स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट (मार्च 2022)
- दिल्ली में शराब आपूर्ति पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट
- स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट (7 मार्च 2023)
- पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विस के मैनेजमेंट पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट
- दिल्ली परिवहन निगम की वर्किंग पर दो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट
- फाइनेंस अकाउंट्स 2021-22
- अप्रोपरेशन अकाउंट्स 2021-22
- फाइनेंस अकाउंट्स 2022-23
- अप्रोपरेशन अकाउंट्स 2022-23

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
15 मार्च 2025

महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल!

फडणवीस-शिंदे के बीच टकराव तेज, कहीं बदल ना जाए महाराष्ट्र का समीकरण!

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उथल-पुथल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तनाव गहराता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा अभी भी बरकरार है और कहा जा रहा है कि अमित शाह पर्दे के पीछे से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच फडणवीस ने शिंदे गुट के कई विधायकों और पूर्व सांसदों की सुरक्षा हटाने का फैसला लिया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। इसके अलावा, उद्योग विभाग और अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर भी दोनों नेताओं में खींचतान जारी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी और शिंदे गुट के बीच दरार इतनी गहरी हो गई है कि इसका असर आगामी चुनावों में भी दिखेगा?

महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सा धमाका हो जाए ये किसी राजनीतिक पंडित को नहीं पता है। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच लगातार बढ़ती तनातनी की खबरें सुर्खियों में हैं। महायुति सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोनों नेताओं के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है। ताजा मामला तब सामने आया जब फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान लिए गए एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी। 3200 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य विभाग की परियोजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। फडणवीस के इस कदम ने शिंदे कैंप को तगड़ा झटका दिया है। यही नहीं वहां नेताओं की बैठकें भी कई चीजों की तरफ इशारा कर रही हैं।

शिंदे के पुराने फैसलों पर फडणवीस की सख्ती

असल में देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान लिए गए कई फैसलों की समीक्षा शुरू कर दी है। सबसे बड़ा मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। जहां 30 अगस्त 2024 को 3,190 करोड़ रुपये का ठेका पुणे की एक निजी कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि बिना किसी ठोस कार्य अनुभव के इस कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका दिया गया था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने तबादलों और एंबुलेंस खरीद में भारी अनियमितता की थी। अब फडणवीस ने इस फैसले को निलंबित कर दिया है और संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में कई अन्य फैसलों पर भी पुनर्विचार हो सकता है।

ओएसडी... पीए की नियुक्ति यों पर भी रोड़ा

सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि शिंदे गुट के मंत्रियों के निजी सहायकों (पीए) और विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) की नियुक्ति में भी अड़चनें आ रही हैं। मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनकी नियुक्तियों में देरी की जा रही है जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। रायगढ़ के पालकमंत्री पद को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एकनाथ शिंदे ने इस पद पर अपने मंत्री भरतशेठ गोगावले का नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन बाद में एनसीपी की मंत्री आदिति तटकरे को यह जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इस फैसले पर भी बाद में रोक लगा दी गई।

समीकरणों में बदलाव के संकेत?

इधर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इससे राज्य में बदलाव की हवा बहने लगी है ।शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में संजय रावत की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ और एनसीपी (शरद पवार)के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बब्बन कूले से हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इसके पहले हाल ही में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और शरद पवार का करीब आना भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत के बाद विपक्ष सदमे में चला गया था, मुख्यमंत्री बने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के दोनों सहयोगी दलों शिवसेना (शिंदे)और एनसीपी (अजीत पवार)को साथ में रखा हुआ है, हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सामजस्य की कमी कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि इसका दोनों तरफ से खंडन किया गया है लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद शिंदे सहज नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में शरद पवार और शिवसेना (उद्धव ठाकरे के साथ सामने आ रहे नए समीकरण शिंदे के लिए और चिंता बढ़ा सकते हैं।

क्या बदल सकता है सत्ता का गणित?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। फडणवीस की तरफ से शिंदे सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और लगातार उनके प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें, फिर नेताओं की मीटिंग्स। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि शिंदे को लेकर बीजेपी अब बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। यह भी संकेत है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने पत्ते अलग तरीके से खेल सकती है। फडणवीस और राज ठाकरे की हालिया मुलाकात से भी नए राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

संजय राउत के दावे से सियासी हड़कंप!

सामना में संजय राउत ने लिखी शाह-शिंदे की बातचीत की स्क्रिप्ट

महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के दावे ने राजनीति को गरमा दिया है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर दावा किया है कि शिंदे की शिवसेना बीजेपी में मिल जाएगी। राउत ने शिंदे की पुणे में अमित शाह से हुई मुलाकात में क्या बातचीत हुई। इसका ब्योरा सामना में लिखा है। राउत का दावा है कि शिंदे खुश नहीं हैं वे फडणवीस की शिकायत अमित शाह से कर रहे हैं ।राज्य सभा सदस्य संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। उन्होंने अपने नाम से प्रकाशित लेख में कहा है कि एकनाथ शिंदे ने 22 फरवरी की सुबह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित 'वेस्टइन' होटल में हुई। राउत ने लिखा है कि 57 विधायकों का नेता अमित शाह से मिलने के लिए सुबह चार बजे तक जागता रहा। 'सरकार में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कल तक मैं मुख्यमंत्री था। आज मेरे सारे फैसले पलट दिए जा रहे हैं', यह बताने के लिए शिंदे ने सुबह चार बजे अमित शाह से मुलाकात की। राउत ने दावा किया है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद जब शिंदे बाहर निकले तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह और शिंदे के बीच चर्चा हुई और उसमें शिंदे का फडणवीस को लेकर शिकायत का स्वर था। राउत ने सामना में लिखा है कि उस चर्चा का जो ब्यौरा संवाद के तौर पर साझा किया है।

अमित शाह : क्या शिंदे जी, सुबह के चार बज रहे हैं, इतना क्या अर्जेंट है?

- **शिंदे :** आपको सब मालूम है, यहां क्या हो रहा है।

शाह : क्या हो रहा है?

- **शिंदे :** मुझे और मेरे लोगों की घेराबंदी करने की कोशिशें खुलेआम चल रही हैं।

शाह : ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देवेंद्र से बात करता हूं।

- **शिंदे :** मुझे दबाने की, खतम करने की पूरी कोशिश हो रही है। आपके भरोसे हम आपके साथ आए। आपका वादा था, चुनाव के बाद भी मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा।

शाह : हमारे 125 लोग चुनकर आए... तो आप वैसा क्लेम कर सकते हो?

- **शिंदे :** मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ।

शाह : नहीं, मोदीजी के चेहरे पर चुनाव हुआ। आपको क्या चाहिए बोलो... मैं कोशिश करूंगा।

- **शिंदे :** मुख्यमंत्री।

शाह : देखो भाई, ये ठीक नहीं है। अभी नहीं हो सकता। पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा।

- **शिंदे :** मैं क्या करूं?

शाह : आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ। आपका क्लेम सीएम पद पर तब रहेगा। बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा। आपका रिस्पेक्ट हमने रखा है।

- **शिंदे :** फिर हमारे पार्टी का क्या?

इस पर 'वो हमारे पे छोड़ दो। वो पार्टी हमने ही बनाई। आप चिंता मत करो।' ऐसा शाह ने कहा और सुबह की यह बैठक समाप्त कर दी। राउत ने दावा किया है कि ऐसा बताने वाले बीजेपी के ही लोग हैं।

(नोट : सूत्रों का हवाला देकर सामना में प्रकाशित अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत।)

चाय पार्टी में क्या बोले शिंदे?

राज्य में संजय राउत द्वारा फोड़े गए बम पर जहां सियासत गर्म है तो वहीं दूसरी ओर बजट सत्र से पहले शाम को महायुति की तीनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कांफेंस की। इस दौरान काफी समय तीनों नेताओं में एक साथ फिर ठहाके लगे थे। शिंदे ने कहा कि फडणवीस और उनके बीच सिर्फ कुर्सी बदली है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ अजित दादा की कुर्सी फिक्स रही। इस पर अजित पवार ने कहा कि आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं कर पाए। तो खूब ठहाके लगे। इस व्यंग्य पर फडणवीस ने कहा कि यह कुर्सी रोटेशन वाली है। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर होने की अटकलें काफी समय से चल रही है। फडणवीस ने इसका खंडन किया है। राजनीतिक विश्लेषक संजय राउत के दावे पर हैरत में हैं। उनका कहना है कि राउत यह दावा उस नैरेटिव को सेट करने का हिस्सा हो सकता है ताकि शिवसेना यूबीटी और न टूटे, क्यों राज्य में लगातार शिवसेना यूबीटी को झटके लग रहे हैं।

पंजाब में गरमाई राजनीति, 'मान नहीं दे रहे ध्यान'

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पहली बार पंजाब में दस्तक

चण्डीगढ़-पंजाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब की आप सरकार एक्शन मोड़ में है। सरकार के तेवर बदले दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि उनकी झुंझलाहट कई सवाल खड़े कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि दिल्ली हार के बाद सीएम मान अंदरूनी तौर पर निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री की इस झुंझलाहट से पंजाबी हैरत में हैं। सीएम की यह झुंझलाहट आप के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब में दस्तक देंगे। इससे प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। पहले जब मनीष सिसोदिया ने पंजाब के स्कूलों का दौरा किया था, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। अब विपक्ष ने केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे का विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में दिल्ली का दखल बढ़ता जा रहा है। सीएम मान इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं, जिस कारण वह अब प्रदेश में दखल बढ़ा रहे हैं। इसके बाद ही लुधियाना पश्चिम हलके से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आप से उम्मीदवार घोषित करने के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई थी कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं।

किसानों की बैठक से उठकर जाने से गरमाई सियासत

पिछले दिनों किसान संगठनों के साथ चल रही बैठक से सीएम के उठकर जाने के प्रकरण ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री भगवंत मान को चारों तरफ से घेर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं की धरपकड़ ने आग में घी डालने का काम किया है। पंजाब सरकार के खिलाफ कई जगह अर्थी फूंक प्रदर्शन किए गए । उगराहां यूनियन के महासचिव दरबारा सिंह ने इसे तानाशाही करार दिया है।

दिल्ली हार के बाद आप का पंजाब पर ही फोकस

दिल्ली हार के बाद आप नेतृत्व चौकन्ना हो गया है और किसी भी हालत में पंजाब पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। यदि पंजाब में पकड़ ढीली पड़ी तो पार्टी के वजूद पर खतरा आ सकता है।

मान का दावा 'कोई विधायक नहीं टूटेगा'

चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब चुनाव के लिए अभी काफी समय बचा हुआ है। इस बचे हुए समय में पंजाब को ऐसा मॉडल बना देंगे कि पूरा देश देखेगा। वहीं चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाने की अटकलें को भी भगवंत मान ने खारिज किया। मान ने दावा किया कि पंजाब में आप का कोई भी विधायक नहीं टूट रहा। सभी पार्टी के साथ हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के बारे में कुछ कहने से पहले दिल्ली में कांग्रेस को अपने विधायकों तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सभी को जनता के मुद्दे की पहचान कर उस दिशा में काम करने को कहा है। मान ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए वह पिछले 75 साल में भी नहीं हुई। बचे हुए समय में पंजाब को विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। शहरों की तरक्की, गांव का विकास होगा। पार्टी में टूट पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जमीन से उभरे हुए नेता है। आप की सरकार पंजाब में व्यापारियों का विश्वास जीतने में कामयाब हुई है। पंजाब में तीन साल में 50 हजार से ज्यादा नौकरी देने में कामयाब हुए। पंजाब में ड्रग्स को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। हर प्रदेश के पास अपना स्थिति होता है। पंजाब में स्कूल मोहल्ला क्लीनिक डिस्पेंसरी बनाने के लिए पर्याप्त जगह है। हम वहां काम कर सकते हैं वहां काम करेंगे।

पंजाब के लोगों के साथ धोखा

पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने दिल्ली में हार के बाद वहां के नेताओं की पंजाब के दखलअंदाजी बढ़ती जा रही है। केजरीवाल का यह दौरा भी उसी का हिस्सा है। खन्ना ने आरोप लगाया कि पिछली कैबिनेट की बैठक की सरकार ने फोटो तक जारी नहीं की, क्योंकि उसमें दिल्ली के कुछ नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। आप दिल्ली के नेता अब पंजाब पर काबिज होना चाहते हैं। खन्ना ने कहा कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली में विधायकों को बुलाया और अब वह पंजाब आकर विधायकों व अधिकारियों की बैठक लेंगे। यह पंजाब के लोगों के साथ धोखा है।

दिल्ली हार के बाद बिखर जाएगी 'आप'

गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। पंजाब को मिड-टर्म (मध्यावधि) चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। रंधावा ने कहा कि आप के 35 विधायक दूसरी पार्टी ज्वाइंन करने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली परिणाम के बाद पंजाब में भी बड़े भ्रष्टाचार निकलेंगे। शराब, धान खरीद में एमएसपी घोटाला सामने आएंगे। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने इस हार को पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक के लिए अपमानजनक हार बताया। खैहरा ने कहा कि यह फर्जी क्रांतिकारियों की ओर से अपनाई गई छल और झूठ की राजनीति की हार है, जो अपने हर वादे से मुकर रहे हैं। ये नतीजे भगवंत मान को भी पंजाब में झूठ और बदले की राजनीति से दूर रहने का संदेश देते हैं।

उपचुनाव में संजीव अरोड़ा के नामांकन पर उठे सवाल

सियासी जानकार मानते हैं कि दिल्ली की दखलंदाजी, पंजाबियों को भा नहीं रही है। इस पर अंकुश लगने से पंजाबियों का भरोसा बढ़ सकेगा। वहीं लुधियाना उपचुनाव में राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतारने पर सवाल उठ रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि यदि उपचुनाव में जीत के बाद दिल्ली के किसी नेता को राज्यसभा में भेजा जाता है तो आप के प्रति आक्रोश पनप सकता है। पंजाब में पार्टी को आम आदमी की साधारण छवि को कायम करना होगा। भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने कहा कि आप नेतृत्व, पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग कर अपने सियासी हित साधने की कोशिश लगातार कर रहा है। पंजाब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली नेतृत्व की दखलंदाजी से पंजाबी खफा हैं और इसका हिसाब पंजाबी जरूर लेंगे। किसानों से सरकार का व्यवहार तो समझ से परे है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में दस्तक दे रहे हैं।

दिल्ली की विवादित आबकारी नीति को लेकर पंजाब में भी सियासत गरमाई

दिल्ली में जिस आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी की हार का कारण माना गया, अब वही मुद्दा पंजाब में भी गरमाने लगा है. अकाली दल के साथ कांग्रेस पूछ रही है कि जिस शराब नीति की वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए, वही शराब नीति तो पंजाब में भी लागू है, तो फिर यहां कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब इसी नीति से दिल्ली में राजस्व का नुकसान हुआ तो यहां कैसे नहीं हो रहा है? दोनों दलों ने पंजाब में भी नई शराब नीति की समीक्षा करने और सीएजी रिपोर्ट पेश करने की मांग की है। इससे मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो नीति दिल्ली में लागू की गई थी, वही नीति पंजाब में आज भी लागू है, जिससे वहां सरकार को फायदा हो रहा है। पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, पिछले दिन दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई है, जिसमें बताया गया है कि नई शराब नीति के चलते दिल्ली सरकार को 2 हजार करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हुआ है। बीजेपी को बताना चाहिए कि इस मामले में दोहरे मानदंड क्यों हैं? दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के तहत मामले दर्ज किए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई को जेल भेजा गया, लेकिन वही नीति पंजाब में भी लागू है। यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई।

चर्चित सेक्स सीडी कांड की इनसाइड स्टोरी

8 साल बाद भी राज...

सीडी किसने बनाई? किसने बंटवाइ?

कारोबारी की मौत, जेल से निकले बघेल सीएम बने और वर्मा सलाहकार

रायपुर। साल 2017-18 में एक सीडी की वजह से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल महसूस किया गया। झटके इतने तेज थे कि भाजपा सरकार की नींव हिल गई। 15 साल से काबिज बीजेपी का कमल मुरझा गया और कांग्रेसी पंजे ने सत्ता की कुर्सी पर कब्जा कर लिया।इस सीडीमें एक अश्लील वीडियो था। पुरुष और महिला के प्राइवेट मोमेंट की क्लिप थी, आदमी के चेहरे की जगह तब के पीडब्यूडी मंत्री राजेश मूणत का चेहरा था। तत्कालीन डॉ रमन सिंह सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी, तब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जेल गए। अब 7 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी सेक्स सीडी कांड के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने 4 मार्च 2025 को कहा है कि बघेल पर कोई केस नहीं बनता। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी किसी नेता की ऐसी सीडी नहीं आई थी। अश्लील सीडी का मामला अब फिर से चर्चा में है। अब भाजपा की सरकार है तो फिर से इस केस की सुनवाई शुरू हुई है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर इस सीडी को फैलाने का आरोप लगाया गया था। भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने रायपुर के पंडरी पुलिस स्टेशन में ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। बजाज ने दावा किया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन करके परेशान किया और कहा कि उसके पास उनके आका की एक सीडी है। इस मामले में भूपेश बघेल के करीबी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को अक्टूबर 2017 में गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास से 500 सीडी और पेन ड्राइव बरामद हुई हैं।

आखिर क्या है छत्तीसगढ़ का सेक्स सीडी कांड?

दरअसल, अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में एक कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। इसे कथित रूप से पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बताया जा रहा था। शिकायत के बाद पुलिस को दिल्ली में सीडी बनाने का इनपुट मिला, वहां से तार पत्रकार और कांग्रेस के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा से जुड़े। तब रायपुर के आईजी रहे प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि वर्मा सीडी बनवा रहे थे, इस दावे के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वर्मा भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उनपर साजिश रचने का आरोप था। इस बीच केस सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद इस कांड में भाजपा के नेता कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, दुर्ग के कारोबारी विजय भाटिया, दिवंगत कारोबारी रिंकू खनूजा, विजय पांडया पर केस दर्ज किया था।2018 के बाद कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, और मामले में आरोपी रहे सीएम बघेल ने सीबीआई को प्रदेश में आने नहीं दिया गया।

भूपेश बघेल ने X लिखा सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद भूपेश ने X पर सत्यमेव जयते लिखा है।

दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था। यह दूसरी बार है, जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी। फिलहाल भूपेश बघेल के अलावा बाकी 4 आरोपियों पर कोई फैसला नहीं आया है, अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

शिकायतकर्ता कौन है?

भाजपा नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर 26 अक्टूबर 2017 को पंडरी थाने में पहला केस दर्ज किया गया। बजाज की दर्ज कराई एफआईआर में ब्लैकमेलिंग का जिक्र है। किसी ने लैंड लाइन से उन्हें फोन पर कहा था कि मेरे पास तुम्हारे आकाओं के अश्लील वीडियो हैं, पैसे दो वर्ना सीडी बनाकर बांट दूंगा।पुलिस ने नंबर को ट्रेस किया दिल्ली की एक दुकान का इनपुट मिला, यहां सीडी रिकॉर्डिंग का काम होता था। यहां से वर्मा और फिर दूसरे आरोपियों का लिंक मिलने की बात सीबीआई और पुलिस करती है। जिन पर केस दर्ज है।

सीबीआई की थ्योरी क्या है, इतने सालों में क्या पता चला?

सीबीआई ने भाजपा नेता कैलाश मुरारका को मुख्य आरोपी बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि कैलाश मुरारका ने श्याम नगर निवासी रिंकू खनूजा और शिवानंद नगर निवासी विजय पांड्या को अश्लील सीडी टेंपर करने के लिए 75 लाख रुपए दिया था।दोनों पैसा लेकर मुंबई गए। वहां फिल्म प्रोड्यूसर मानस साहू से मिले, जो मूलत॰ ओडिशा का रहने वाला है। वह मुंबई में फिल्म बनाता है। उसे अश्लील वीडियो टेंपर करने के लिए 98 हजार रुपए दिए गए।मुंबई के एक स्टूडियो में वीडियो टेंपर किया गया। मानस साहू अश्लील वीडियो में पूर्व मंत्री का चेहरा लगाया फिर वही टेंपर वीडियो सीडी और पैन ड्राइव में विजय और रिंकू को दिया। उसे लेकर दोनों रायपुर आए। फिर इस वीडियो की आड़ में ब्लैकमेलिंग की कोशिश की।अश्लील सीडी वायरल करने की साजिश के आरोप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। तब वो दो सप्ताह जेल में रहने के बाद बाहर आ गए थे।

एक कारोबारी ने सुसाइड कर लिया ?

इस मामले में सबसे अहम कड़ी श्याम नगर निवासी ऑटो मोबाइल कारोबारी रिंकू खनूजा था। 6 जून 2018 को रिंकू ने खुदकुशी कर ली। खनूजा की मां ने तब मीडिया में आरोप लगाया था कि सीबीआई वाले लगातार पूछताछ कर रिंकू को प्रताड़ित कर रहे थे।सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि रिंकू खनूजा और विजय पांड्या ने सीडी बनवाई। सीडी कांड के सरकारी गवाह और रिंकू के भाई कारोबारी लवली खनूजा ने भी सीबीआई को बताया है कि 23 अगस्त को रिंकू ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया था।

सेक्स सीडी कांड का राजनीतिक असर

जानकारों का मानना है कि प्रदेश में तब की भाजपा सरकार के प्रति नेगेटिव माहौल बनाने का काम तो इस सीडी ने किया। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि इसी की वजह से सरकार बदली। दरअसल सीडी की चर्चा, बघेल का जेल जाना। इन घटनाओं ने उस वक्त कांग्रेस को प्रदेश में सियासी तौर पर चार्ज किया।कार्यकर्ताओं में बघेल की गिरफ्तारी से जोश आया। बघेल ने शुरू के सप्ताह में वकील नहीं किया किसी सेनानी की तरह खुद को इस केस में पेश करने का प्रयास करते दिखे। लेकिन राजेश मूणत इस वीडियो क्लिप मामले से चर्चा में आए, चर्चा नकारात्मक साबित हुई। नतीजे भी मूणत मंशानुरूप नहीं रहे। बहुत ज्यादा नहीं मगर कुछ हद तक सीडी कांड का राजनीतिक असर हुआ तो था।

करीब 6 साल जांच बंद क्यों रही ?

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्स सीडी कांड में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नोटिस जारी कर सीएम भूपेश बघेल से पूछा था कि इस मामले को दूसरे राज्य में सुनवाई के लिए क्यों न भेज दिया जाए।इस मामले में शिकायतकर्ता प्रकाश बजाज ने बताया कि इस केस में प्रभावशाली लोग आरोपी थे, प्रदेश में कांग्रेस कार्यकाल में हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम बयान बदलें। इसलिए केस को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की गई थी।इस बीच सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री बैन कर दी थी। अब फिर से प्रदेश में आई भाजपा सरकार ने ये प्रतिबंध हटाया है। सीबीआई ने छानबीन शुरू की है, प्रदेश की स्थानीय अदालत में सुनवाई हो रही है।

अब अब आगे क्या होगा ?

केस में कुल 6 आरोपी थे भूपेश बघेल, रिंकू खनूजा, कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। रिंकू खनूजा ने खुदकुशी कर ली थी। बाकी के बचे 4 आरोपियों को लेकर अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2025 को होगी।

तो अब तक क्या साबित हुआ ?

2018 से जारी इस केस में 2025 तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कोई जेल में भी नहीं है। सीबीआई की दलीलों पर किसी को सजा या जेल भेजा गया हो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ साल 2018 के अंत में कुछ दिन विनोद वर्मा और भूपेश बघेल को जेल भेजा गया था। अब तक ये राज बरकरार है कि सीडी किसने बनाई ? किसने बंटवाई ?

सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान...

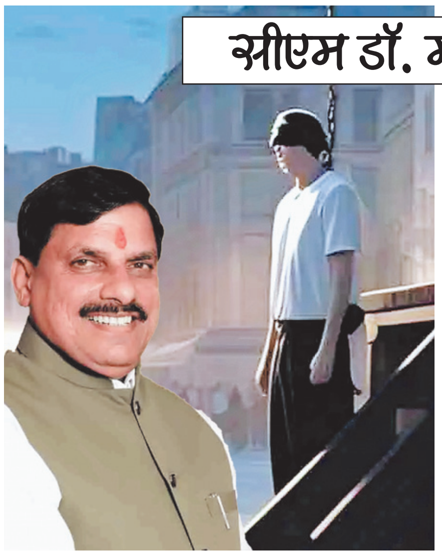

धर्मांतरण करवाने वालों को अब होगी फांसी की सजा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वालों के लिए राज्य में फांसी की सजा का प्रावधान है और अब धर्मांतरण करने वालों को भी फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में मासूम बालिकाओं के साथ दुराचार करने के मामले में सरकार बहुत कठोर है। इस संबंध में फांसी का प्रावधान किया गया है। जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसे छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं।

जो धर्मांतरण कराएंगे, उनको भी फांसी की सजा दिलाए जाने का प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि किसी भी हालत में धर्मांतरण और दुराचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की समाज विरोधी व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि समाज के अंदर कुरीतियों, गलत बातों को बढ़ावा देने से कठोरता के साथ पेश आएंगे। धर्मांतरण मामले में फांसी के प्रावधान किए जाने को लेकर सीएम मोहन यादव के ऐलान पर भोपाल की महिलाओं ने खुशी जताई है और कहा है कि यह एक बेहतर कदम है। कई बार बच्चियों को दूसरे धर्म के युवा बहला फुसलाकर या दबाव में लाकर गलत काम करते थे। मोहन यादव सरकार के इस कानून के बाद इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। मध्य प्रदेश यह कानून लागू होने पर ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन जाएगा।

मुसीबत में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पत्नी ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए है। सिंघार की पत्नी प्रतिभा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने अपने पति पर उनकी कथित महिला मित्र की जान लेने का आरोप लगाया है। प्रतिभा मुदगल ने कहा है कि सिंघार ने एक आईपीएस अधिकारी का सहयोग लेकर इस घटना को दूसरा रूप दिया गया है। दरसअल, मामला 2021 का है। उमंग सिंघार के बेडरूम में सोनिया भारद्वाज का शरीर मिला था। महिला की मौत के मामले में उमंग सिंघार की पत्नी ने सवाल उठाए है। उन्होंने मामले में एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए है। याचिका में मुदगल ने कहा है कि मृतक सोनिया के बेटे ने डीजीपी को एक पत्र लिखा था। पत्र में बेटे ने कहा था की उसकी मां की जान ली गई है। सिंघार और पुलिस ने मिलकर मामले को दूसरा रूप दिया है। इतना ही नहीं उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी के वकील ने भी गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा है कि सिंघार और उनके कुछ समर्थक नेताओं का एक गिरोह है जो हाई-प्रोफाइल महिलाओं को फंसाकर उनका शोषण करता है। आपको बता दें कि उमंग सिंघार के बेडरूम में सोनिया का शव मिला था। घटना 2021 की है। मामले की शुरूआती जांच में सोनिया की हत्या होना बताया था, लेकिन बाद में मृतक के बेटे के लिखे डीजीपी को पत्र में मामला जान लेना बताया था।

खुल सकती है वीडी के नाम की लाटरी

राजनीतिक हलकों में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर निर्णय का इंतजार है। पहले जिलाध्यक्षों के चुनाव के कारण विलंब हुआ। इसके बाद दिल्ली चुनाव के कारण फैसला टला। अब कहा जा रहा है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ में प्रदेश के दौरे पर थे तब सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रदेश को नया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जल्दी मिलेगा। इसके बाद वीडी शर्मा के स्थान पर नए नेता की ताजपोशी तय मानी जाने लगी थी। दौड़ में शामिल नाम अब भी चर्चा में हैं। पर वीडी शर्मा के अपने प्रयास जारी रहे। एक बार उनका कार्यकाल बढ़ चुका है। इस बीच भाजपा नेतृत्व ने पड़ोस के छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष रिपीट कर दिए। छत्तीसगढ़ में किरण सिंह जूदेव और राजस्थान में मदन राठौड़ को एक और मौका देकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर मप्र में भी उनके नाम की लाटरी खुल सकती है।

पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने छोड़ा खुरई

मध्यप्रदेश की राजनीति से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने अचानक अपना क्षेत्र खुरई छोड़ने का फैसला कर लिया है। खुरई छोड़ने का मतलब यह नहीं की वे खुरई नहीं जाएंगे। खुरई छोड़ने का मतलब उन्होंने अपना और अपने परिवार का नाम मतदाता सूची से हटवा दिया है। भूपेन्द्र सिंह ने अपना और अपनी पत्नी सरोज सिंह, उनकी बेटी उपमा सिंह, काजल सिंह, अनुप्रिया सिंह और बेटे अभिराज सिंह का नाम अब खुरई की मतदाता सूची से हटवा दिया है। अब ये सभी नाम नरयावली विधानसभा की बामोर ग्राम पंचायत में शामिल कराया गया है। पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह वर्तमान में खुरई से विधायक है, भले ही वे मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अभी उनका करीब साढ़े तीन साल का खुरई विधायक का कार्यकाल बाकी है।

अकल चबूतरे से

बचना जरा इमोशनल अरेस्ट करने वालों से

व्यंग्य मुकेश राठौर

जब से स्मार्ट फोन आया, आदमी भयंकर स्मार्ट हो गया है। इतना स्मार्ट कि बिना खड़ग, बिना ढाल हजारों मील दूर बैठकर फोन से फोन पर आपको बंधक बनाने जैसा कमाल कर रहा है। क्यों न करे? नया इंडिया है मोबाइल में घुसकर मारता है। आप फोन कॉल आने पर हेलो भर कहने जाते हैं और 'ये लो', 'ये भी लो' करते-करते हाउस लोन संबंधी किस्तों की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं।

स्मार्ट लैंग्वेज में इसे 'डिजिटल अरेस्ट' करना कहते हैं। कभी तो लगता है देश में जितने असल अपराधी अरेस्ट नहीं हो रहे, उससे कहीं ज्यादा बेचारे निरपराध लोग अकारण अरेस्ट हुए जा रहे हैं। किए की सज़ा पर उतना दुख नहीं होता, जितना बिन किए मिली सज़ा पर होता है। डिजिटल अरेस्ट के बरअक्स समाज में 'इमोशनल अरेस्ट' की घटनाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। इमोशनल अरेस्ट माने भावनात्मक रूप से किसी को बंधक बनाना। अनुभव कहता है भावुक आदमी जल्दी बंधक बन जाता है। बगैर जंजीरों के कच्चे धागों से। बस लपेटते रहिए वह लिपट जाएगा फिर सामने वाला गले लगाए, चाहे गला दबाए, उसकी मर्जी इमोशनल अरेस्ट करने वाले भी आप पर महीनों बल्कि बरसों नज़र रखते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट करने वालों की तरह अपरिचित नहीं होते बल्कि आपके अपने जाने-पहचाने, दोस्त-मित्र, नाते-रिश्तेदार होते हैं। वे पहले जां, फिर जाने जां, फिर जाने जाना होते हुए आपके दिल के मेहमां हो जाते हैं। जब कोई आपकी हर बात को पसंद करने लगे, दूसरों की तुलना में आपको श्रेष्ठ बताए, आपकी ही तरह स्वयं को भी सिद्धांतवादी बताए, आपके एक इशारे पर सारे काम छोड़कर आ जाए, आप आधी रात को बाइक से कन्याकुमारी चलने को कहे और वह चल दे, आपके दिए दस रुपये से साढ़े आठ का सामान खरीदकर डेढ़ रुपया मय हिसाब लौटाए तो सम्भल जाइए भाई साहब, ये इमोशनल अरेस्ट के सिम्प्टम्स हैं। अचानक एक दिन वह कल तक के लिए कुछ रुपये उधार मांगेगा, आप इमोशनल अरेस्ट होकर सहर्ष उसकी मदद करेंगे। फिर वही होता है जो होता आया है। हर कल, कल बन जाएगा। कल-कल करते आज, हाथ से छूटे सारे टाइप पैसा तो गया ही आदमी भी हाथ से चला जाता है। आप 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना' गाते रहेंगे और वह 'चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन से देश' चला जाता है जहां फोन भी नहीं लगता। फोन लगता भी है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं मगर आपकी आवाज नहीं सुनाई देती। बहरहाल, डिजिटल अरेस्ट हुए लोगों की मदद के लिए साइबर सेल और हेल्प लाइन नंबर हैं लेकिन इमोशनल अरेस्ट के मारों की मदद करने वाला कोई नहीं। कहीं कोई हो तो बताइएगा।

कही-सुनी

कीर्ति राणा

बीआरटीएस तोड़ने का भी टेंडर....!

बीआरटीएस हटाने संबंधी कोर्ट के फैसले के बाद जब से निगमायुक्त ने यह कहा है कि बीआरटीएस तोड़ने के लिए टेंडर जारी करेंगे, शहर के आम नागरिकों को समझ नहीं आ रहा है कि यह काम भी टेंडर से किसी निजी एजेंसी से ही कराना है तो नगर निगम में अतिक्रमण विरोधी दस्ते वाली फौज किस काम के लिये है। यह काम नियमित वेतन ले रहे निगमकर्मियों से क्यों नहीं कराया जा सकता। नगर निगम में आए दिन उजागर होने वाले घोटालों पर आश्चर्य व्यक्त करने वालों को इस टेंडर वाली प्रक्रिया से समझ आ गया है कि पूरे कुए में ही भांग पड़ी हुई है।जिन भवनों में नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण पाए जाने पर लाल निशान लगा देते हैं या सड़क चौड़ीकरण में जितना हिस्सा बाधक होता है उतना हिस्सा तोड़ने वाली निगम गैंग के अनुभवियों को भी तो बीआरटीएस तोड़ने के काम में लगाया जा सकता है? टेंडर निकालने की जरुरत क्या है, यह चिंता शहर के लोगों में तो है लेकिन निगम परिषद में ना सत्ता और न विपक्ष के पार्षदों में जुबान हिलाने की हिम्मत है।

खंडवा में तोता उड़....

खंडवा में वन विभाग ने गुलाब के छल्ले वाले 27 तोते (रेड रोज पैरा किट) के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों तस्कर तोतों को पिंजरे में कैद कर एक तोता महज 25 से 30 रुपए में बेचते थे। वन विभाग की टीम ने सभी 27 तोतों की स्पेशल कोर्ट में पेशी कराई। जज ने आरोपियों को तो जेल भेज दिया। तोतों की आजादी को लेकर फैसला यह हुआ कि तोतों को शहर के बाहर एक खेत पर खुली हवा में छोड़ दिया जाए।

पलक के पच्चीस साल

पच्चीस साल पहले छोटे से बहन-भाई ने गीत गाकर, चैरिटी शो वाला 'दिल से दिल तक' अभियान उन बच्चों के लिये शुरु किया था जिनके हार्ट में छेद होने और महंगी सर्जरी के कारण जिनके अभिभावक इन बच्चों का इलाज कराने में सक्षम नहीं थे।अब बॉलीवुड की स्टार सिंगर पलक और उनके भाई पलाश तब से अब तक 3,473 बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।बहुत संभव है कि मार्च अंत में दोनों बहन भाई एक शो इंदौर में करने आएं। 'दिल से दिल तक' अभियान में पहले दिन से इस परिवार से जुड़े सुनील जैन शो अरेंज करने के लिये सक्रिय हुए हैं।

लड़ाई-लड़ाई माफ करो.....

दो बच्चों में जब झगड़ा और रुसा फूगी की नौबत आ जाती थी तब कोई तीसरा बड़ा दोनों को समझाते हुए कहता था लड़ाई-लड़ाई माफ करो....। कुछ ऐसा ही रोल गत दिनों भोपाल यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा है। दिल्ली रवाना होने से पूर्व एयरपोर्ट पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अलग ले जाकर कुछ समझाया। खबर ये उड़ी कि विजयवर्गीय को और अधिक पॉवरफुल कर सकते हैं। अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं, हां इतना जरुर हुआ है कि सम्पन्न हुई जीआइएस की सरकार की तरफ से विजयवर्गीय ने ब्रीफिंग जरुर की है।यह बदलाव इसलिए नोटिस किया गया कि विजयवर्गीय ने लंबे समय से ब्रीफिंग करने से खुद को अलग कर लिया था और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल यह काम कर रहे थे। मंत्रिमंडल की बैठकों में भी वे कई बार ऐसीटिप्पणी करने से नहीं चूकते थे जो सरकार केलिये परेशानी बढ़ा देती थी। शाह जी की समझाइश का ही असर रहा कि विजयवर्गीय ने महिला दिवस पर अपने एक नंबर विधानसभा क्षेत्र में महिला पहलवानों का अंतरराष्ट्रीय दंगल कराया उसमें सीएम डॉ यादव भी दौड़े दौड़े चले आए। छावनी में कड़ाव का दूध पीने वाला प्रसंग छोड़ दें तो सीएम का इंदौर में यह सिंगल कार्यक्रम था जबकि सीएम जब भी किसी शहर में पहुंचते हैं तो दो-चार कार्यक्रम जुड़ ही जाते हैं। महिला दंगल के इस आयोजन से यह भी स्पष्ट हो गया कि जिस तीन नंबर क्षेत्र से कभी आकाश विजयवर्गीय विधायक रहे अब उस क्षेत्र में आकाश की कोई दखलंदाजी नहीं है। अब वे पिता के विधानसभा क्षेत्र की सारी प्लॉनिंग को अंजाम देने में लगे हैं।यही कारण है कि केके गोयल अब इस विधानसभा को लेकर उतने व्यस्त नहीं रहते।

जमीन वाले बाबाजी !

बाबा रामदेव को मप्र में जमीन देने में सरकार उदारता दिखाए और बाबाजी उद्योग नहीं लगाएं तो कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिलेगा ही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जैन का कहना है शिवराज सिंह सरकार के वक्त 2016 में हुई जीआइएस में बाबा को पीथमपुर में 40 एकड़ जमीन दी गई थी, 500 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग प्लांट आज तक नहीं लगा, रोजगार कहां से मिलता। अभी भोपाल में हुई जीआइएस में इस सरकार ने बाबा रामदेव को फिर 432 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। यहां कब उद्योग शुरु होगा यह पूछना तो दूर सरकार ने बाबाजी से यह तक नहीं पूछा कि पीथमपुर वाली 40 एकड़ जमीन का उपयोग क्यों नहीं किया अब तक।

शिव-साधना का डांस

घर में ब्याव मंडा हो और मां-बाप खुशी जाहिर ना करे ऐसा संभव है क्या? राजनीतिक जीवन में भले ही शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हों लेकिन कार्तिकेय की विवाह रस्मों में महिला संगीत में वो बेटे के विवाह की खुशी पत्नी साधना सिंह के साथ डांस करके तो जाहिर कर ही सकते हैं। ऐसे आनंद के अवसर बार बार तो आते नहीं।सीएम रहते भजन में मगन शिव-साधना के डांस की रील खूब वॉयरल हो रही है।

कचरे से किताब तक...

इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने कचरा जलाए जाने के दौरान पीथमपुर की रामकी कंपनी में मौजूद रहने का अपना वादा निभाया है। उनकी इस मुस्तैदी की सरकार ने तारीफ भी कर दी है। इस कचरे को लेकर वो किताब लिखने का मन तो बना रहे हैं लेकिन घर पहुंचते ही मैडम की चेतावनी बार बार याद आ जाती है कि जब जब आप की किताब प्रिंट होने की प्रक्रिया में रहती है, ट्रांसफर आर्डर आ जाता है।

प्रशासनिक अमले में भव्य आतंक !

भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सरकारी बाबू को चपरासी बनाने वाली खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल के एक बार फिर सख्त तेवर देखने को मिले हैं। इस महिला आयएएस अधिकारी ने अब स्कॉलरशिप स्कैम के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक, डीडीओ क्रिएटर और लेखा प्रभारी ने मिलकर 84 लाख 39 हजार 977 रुपये का डिजिटल सिग्नेचर और खातों में हेरफेर कर गबन किया था। कलेक्टर भव्या मित्तल ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई और वसूली के आदेश दिए हैं।

बिल्ली रास्ता काट गई...

कहां तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार चालू होने वाले विधानसभा सत्र में सौरभ शर्मा मामले में सरकार के लिये मुसीबतें खड़ी करने वाले थे। उससे पहले उनकी पत्नी ने महिला मित्र वाले केस में सिंगार की मुख्य भूमिका का आरोप लगा कर उन्हें बेकफुट पर जाने के लिये मजबूर कर दिया।उन्हें समझ भी आ गया है कि पत्नी को भड़काने में भाजपा की भूमिका कितनी है, तभी तो वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष यह ना भूलें कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं।

चर्चा में तो यह विवाह भी है

पूर्व मंत्री-भाजपा नेता संजय पाठक के पुत्र के विवाह समारोह के कार्यक्रम कितने भव्य रहे यह धड़ाधड़ वॉयरल होती रील्स बता रही हैं। इस समारोह से जुड़ी एक खास बात यह भी कि इंदौर से बॉबी छाबड़ा मित्र मंडली ने भी खूब रंग जमाया।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67